पानी के लिए आज़ाद नगर के मज़दूरों का विजयी संघर्ष

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बूंद-बूंद पानी को तरस रहे, दिन भर 12-12 घंटे पसीना बहाकर, महीने में बा-मुश्किल 10,000/ कमाने वाले, उसमें से 3000/ हर महीने, टैंकर से पानी ख़रीदने में खर्च करने को मज़बूर, आज़ाद नगर, सेक्टर 24, फ़रीदाबाद के मज़दूरों ने, 2 जुलाई को, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' के बैनर तले, एक शानदार मोर्चा निकाला। 'बहुत सह चुके अब और नहीं', इस उद्घोष के साथ, 500 से भी ज्यादा मज़दूरों के इस आक्रोश मार्च में, बड़ी तादाद में महिलाएं अपने बच्चों के साथ शरीक़ हुई। तेज़ लू और उमस वाली, बेचैन करने वाली गर्मी की परवाह न कर, आज़ाद नगर मज़दूर बस्ती के लोग, हाथों में लाल झंडे लिए और गले में तख्तियां लटकाए, सुबह 10:30 बजे, पैदल ही अपने घरों से निकल पड़े और यह मोर्चा 11:30 बजे, सेक्टर 8 स्थित, हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा के दफ़्तर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया।

जैसा अपेक्षित था, मंत्री जी, अनुपस्थित थे। उनके बड़े भाई, टिप्पर चंद शर्मा ने, आक्रोशित महिलाओं के उग्र तेवर को भांपने में बिलकुल देर नहीं की और मंत्री के निजी सचिव को, ज्ञापन स्वीकार करने के लिए भेजने की बजाए, मुस्कुराते हुए, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन, हाथ जोड़कर स्वयं सभा के सम्मुख प्रकट हो गए। 'आपकी बस्ती में हर रोज़ पानी उपलब्ध कराना हमारी ज़िम्मेदारी है। पानी 5 दिन बाद आएगा, ऐसा किसने बोला, उस अधिकारी का नाम बताया जाए'। 'आप अंजान और मासूम मत बनिये, आपको सब मालूम है',आन्दोलनकारी महिलाएं, यूं बहलने के मूड में बिलकुल नहीं थीं। तब उन्होंने, वहीं सबके सामने, जल विभाग के सम्बंधित अधिकारीयों को फोन किए और भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच, सभा में घोषणा की 'आज़ाद नगर में, हर रोज़, कम से कम एक घंटा (2 घंटे आएगा, पहले ये बोला था) पानी सप्लाई ज़रूर होगी। तीन बंद पड़े ट्यूब वेल को तत्काल चालू किया जाएगा और उनमें से कोई भी ट्यूब वेल, अगर चालू होने की स्थिति में नहीं हुआ तो उसकी जगह नया ट्यूब वेल लगाया जाएगा। अब तो तालियाँ बजा दो!!'

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के अध्यक्ष कॉमरेड नरेश एवं महासचिव कॉमरेड सत्यवीर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ाद नगर के मेहनतक़श लोग, अपने विधायक-मंत्री को, जो उन्हें भूल चुके हैं, सबसे पहले तो ये बताने आए हैं कि हमीं लोगों ने आपको विधायक चुना है। विधायक चुने जाने के बाद ही आप कैबिनेट मंत्री बन पाए। भाजपा की डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार में, आज़ाद नगर और 60 अन्य मज़दूर बस्तियों में रहने वाले,15 लाख मज़दूर, बूंद-बूंद पानी को मोहताज़ है। मोदी सरकार, 9 साल पूरे होने की, किस बात की गौरव रैलियां निकाल रही है?

केंद्र, हरियाणा और नगर निगम में सत्ता में बैठे, भाजपाईयों और उनके निकम्मे प्रशासन की संवेदनहीनता का ये आलम है, कि लोग टैंकरों से पानी ख़रीद रहे हैं और तीन ट्यूब वेल ठप्प पड़े हैं। वे ठप्प न पड़े होते, तो जल-माफ़िया, हर रोज़ करोड़ों रुपये, इन भूखे ग़रीबों की जेबों से कैसे निकालता!! फ़रीदाबाद को 'उद्योग नगरी' बनाने वाले ये 15 लाख मज़दूर ही हैं, जो पानी की बाल्टियां बीस-बीस रुपये में टैंकरों से ख़रीदने को मज़बूर हैं।

अगर ये निवासी इकट्ठे होकर, अपने हक़ों के लिए लड़ना नहीं सीखे, तो अपनी झोपड़ियों में भूखे-प्यासे ही मर जाने वाले है। मौजूदा भाजपा सरकार से ज्यादा मज़दूर-विरोधी, जन-विरोधी और सरमाएदारों की ऐसी खिदमतगार सरकार आज तक नहीं आई। मंत्री जी की ओर से हुई घोषणाओं की रिकॉर्डिंग की गई है, और पानी की समुचित आपूर्ति होने तक, ये संघर्ष ज़ारी रहेगा।

पानी आया नलों में, ख़ुशी आई चेहरों पर

कितनी भी छोटी हो, जीत का अपना अलग ही ज़ायका होता है। मोर्चे के अगले दिन, 3 जुलाई को, आज़ाद नगर की सूख चुकी टंकियों से, जैसे ही जल-धारा बही, बस्ती के लोग ख़ुशी से झूम उठे। मंत्री के भ्राताश्री का गिरेहबान पकड़ने को तैयार महिलाओं के चेहरे पर ख़ुशी देखने लायक़ थी। तब से सभी लोगों को अपनी संगठन- शक्ति पर विश्वास क़ायम हो गया है। बस्ती ने तय किया है कि सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे की कहीं भी, टूटी टंकियों से पानी बहता ना रहे। साथ ही लोग ये भी अहद कर चुके हैं कि अपने संगठन का विस्तार हर मज़दूर बस्ती में करेंगे। अपने जायज़ हक़ों को पूरा करने और एक बेहतर समाज बनाने की जद्दोजहद में पूरी शिद्दत से जुटेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा ने मांग की है:

1) फ़रीदाबाद प्रशासन एवं हरियाणा सरकार, सर्वोच्च प्राथमिकता पर आज़ाद नगर तथा सभी मज़दूर बस्तियों में, रोज़, पर्याप्त जल-आपूर्ति की व्यवस्था करे। आज़ाद नगर में कम से कम 2 ट्यूब वेल लगाए जाएं, साथ ही सेक्टर 25 स्थित जल-घर में पर्याप्त जल भंडारण की व्यवस्था तत्काल की जाए।

2) फ़रीदाबाद प्रशासन और हरियाणा सरकार ये स्वीकार करें, कि मज़दूर भी इंसान हैं। यह देश संविधान से चल रहा है। मूलभूत नागरिक सुविधाओं, यहां तक कि जीवनावश्यक पानी-आपूर्ति के मामले में भी अमीर-ग़रीब में भेदभाव करना अन्यायपूर्ण व असंवैधानिक है। फ़रीदाबाद नगर निगम द्वारा दिए गए जवाब से, हम सब बेहद आक्रोशित एवं दुखी हैं। मज़दूर भी, हर वस्तु पर, समान दर से जीएसटी देते है।

3) पानी के अवैध कारोबार के सरकारी संरक्षण पर सख्ती से रोक लगे। जल-माफ़िया के सामने प्रशासन इतना लाचार क्यों नज़र आता है? यदि लोगों को पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, तो कोल्ड ड्रिंक कंपनियों पर रोक लगे क्योंकि ये कंपनियां अपने निजी मुनाफ़े के लिए, प्रचंड मात्रा में पानी बर्बाद करती हैं। जल-माफ़िया और नगर निगम का जल आपूर्ति विभाग लूट की कमाई में मिले हुए हैं, और इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इस अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील मामले की जांच की जाए और सभी कसूरवारों को दंडित किया जाए।

4) सेक्टर 25 जल-घर में जल आपूर्ति को नगर निगम के अधिकारी नहीं बल्कि एक पार्षद नियंत्रित करता है और जल-आपूर्ति में भेदभाव हो रहा है। आज़ाद नगर के नागरिक भयंकर गुस्से में हैं। अगर ये अन्याय इसी तरह ज़ारी रहा तो शांति भंग होने की आशंका है। नगर निगम प्रशासन इस अन्याय को तत्काल रोके।

5) औद्योगिक महानगर, फ़रीदाबाद में पानी की मौजूदा एवं भविष्य की संभावित ज़रूरत के अनुरूप विस्तृत जल-भंडारण, संरक्षण तथा आपूर्ति की मास्टर योजना बने।

जिम्मेदार कोई महकमा नहीं सीधे सरकार होती है

फ़रीदाबाद की लगभग 24.5 लाख आबादी की पानी की मांग 450 मिलियन लीटर प्रतिदिन है जबकि आपूर्ति 350 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। पानी उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी एफएमडीए, एमसीएफ और हूडा की है। फ़रीदाबाद महानगर विकास निगम', पानी को शहर में मौजूद भंडारों तक पहुंचाता है। घर-घर उपभोक्ता तक पानी पहुंचाने की ज़िम्मेदारी नगर निगम की है। संकट की स्थिति में ये व्यवस्था, किसी भी विभाग के लिए, ज़िम्मेदारी दूसरे विभाग पर धकेलना आसान बनाती है। पानी न मिलने से बौखलाए लोगों को, क़सूरवार विभाग को पहचानना मुश्किल है, इसीलिए क्रोध का नज़ला कई बार ग़लत अधिकारी पर भी उतर जाता है। नगर निगम बल्लभगढ़ के अधिशासी अभियंता से, जब पूछा गया कि यमुना तट पर कुल कितने रैनीवेल काम कर रहे हैं, तो उनका जवाब था, 'मेरे पास ऐसे सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है।' 'हमें ये जानकारी इसलिए चाहिए क्योंकि 'मज़दूर मोर्चा' के ज़रिए इस समस्या को लोगों की नज़र में लाना है जिससे सरकार पर दबाव बने', व्हाट्सेप पर भेजे गए इस सन्देश का 5 घंटे बाद आया उत्तर है; 'एफ़एमडीए' से संपर्क करो'। 'एफ़एमडीए' फ़ोन नहीं उठाता।

मूल रूप से ज़िम्मेदार है, हरियाणा सरकार, जिसे यह मालूम होते हुए भी कि हर रोज़ पानी की 100 मिलियन लीटर की कमी है, उसे दूर करने के बारे में बिलकुल गंभीर नहीं है। उसकी दिलचस्पी घोषणा करने, फीता काटने, फोटो खिंचवाकर झांकी जमाने में है। घोषित योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे होगा, पिछली योजना का क्या हश्र हुआ, ये कष्ट-साध्य काम करने में, सरकार की कोई रुचि नहीं। कांग्रेस अथवा इनेलो की सरकारें भी, आम जन-मानस की जीवन-मरण की मूलभूत समस्याओं के प्रति संवेदनहीन ही रही हैं लेकिन मौजूदा भाजपा की ट्रिपल सरकारों ने संवेदनहीनता के पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।

फ़रीदाबाद महानगर की पानी की समस्या का समाधान करने के मक़सद से, 'रैनीवेल परियोजना', 500 करोड़ के बजट से 2012 में शुरू हुई थी जिसके तहत, यमुना के तटीय क्षेत्र में कुएं खोदे जाने थे, जिनमें नैसर्गिक तरीक़े से बरसात का पानी इकठ्ठा होगा और फिर उसे पाइप लाइन के ज़रिए फरीदाबाद शहर को सप्लाई किया जाएगा। 13 सितम्बर 2018 को मुख्यमंत्री ने नई घोषणा की कि फ़रीदाबाद, गुडगांव के बाद दूसरे नंबर का बड़ा शहर है इसलिए यहां 'फ़रीदाबाद महानगर विकास निगम (एफएमडीए)' बनेगा। मार्च 2022 में, दूसरी घोषणा हुई कि यमुना तट पर 12 नए रेनीवेल बनाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 120 मिलियन लीटर प्रतिदिन की होगी जिन्हें 2 साल में पूरा किया जाएगा और 120 करोड़ की इस परियोजना को फ़रीदाबाद महानगर विकास निगम देखेगा। इन रैनीवेल का आज क्या हाल है, कुल कितने बने, कितने काम कर रहे हैं; इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं!!

फ़रीदाबाद महानगर में कुल 1411 सरकारी और 88 निजी ट्यूब वेल्स हैं। नगर निगम के पास 215 टैंकर हैं। नगर निगम की फाइलों में, पानी उपलब्ध कराने के लिए 18 एटीएम भी हैं, जिनसे 1 रु प्रति लीटर की दर से पानी ख़रीदा जा सकता है, लेकिन ज़मीन पर, पानी के ये एटीएम आज तक नज़र नहीं आए। पानी बेचने के लिए कुल कितने निजी टैंकर हैं, आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कुल कितने निजी बोरिंग हैं, कुछ पता नहीं। सरकारी पानी की आपूर्ति के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, तो निजी टैंकरों को असीमित जल कैसे उपलब्ध हो जाता है? 800- 1000 प्रति टैंकर का रेट है; कभी भी आर्डर कीजिए, आधे घंटे में टैंकर हाज़िर!! पानी की कमी है, टैंकर नहीं आएगा, कभी भी ऐसा जवाब क्यों नहीं मिलता? एक तरफ़ बूंद-बूंद पानी को तरसते, आपस में झगड़ते-चीखते- चिल्लाते लोग, दूसरी तरफ़ बड़ी-बड़ी कोठियों में हरे-भरे लॉन और गार्डन को, आराम से पाइप से सींचते, कुत्तों को नहलाते लोग!! इस विरोधाभास को पानी का वर्ग-विभाजन न कहें, तो क्या कहें?

मोर्चे में शरीक़ मज़दूर, ये तख्तियां लिए हुए थे; 'आज़ाद नगर को पानी 5 दिन में मिलेगा- खट्टर सरकार शर्म करो', 'हरियाणा सरकार, पानी दो या इस्तीफा दो', 'डबल इंजन की सरकार- मज़दूरों पर दोहरी मार', आज़ाद नगर में पानी नहीं, मोदी-खट्टर शर्म करो', 'पानी का करो इंतज़ाम- वर्ना होगी नींद हराम', 'पानी का इंतज़ाम करो- हिन्दू मुस्लिम में बांटना बंद करो', 'मज़दूर भी इंसान हैं- घरों से निकलो साबित करो', 'मिलकर लड़ना नहीं सीखे तो आगे पछताना होगा', 'अंधी बहरी ये सरकार- नहीं चुनेंगे अबकी बार', 'मज़दूर बस्तियों में पानी नहीं- स्मार्ट सिटी की लफ्फाज़ी बंद करो', 'मज़दूर बस्तियों में पानी दे नहीं सकते- अमृत काल की बकवास बंद करो'।

सभा को, पूर्व पार्षद जगदीश तथा युवा छात्र नेता सनी बादल ने भी संबोधित किया। नगर निगम जल-घर पर मोर्चा, अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रतिनिधिमंडल और मंत्री के दफ़्तर पर हुए कार्यक्रम को क़ामयाब बनाने में, आज़ाद नगर की युवा टीम, मुकेश, चंदन, हैदर अली, वीर सेन, महेश, नरेश, विनोद, बबलू और क्रांति ने बहुत मेहनत की।